

मई, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात् लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। वे 1964 से 1966 तक अपने पद पर रहे। उनके काल में भारत आंतरिक स्तर पर आर्थिक संकट की समस्या से जूझ रहा था, जबकि बाह्य स्तर पर उसे अपने निकटस्थ पड़ोसी पाकिस्तान के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री अपनी आंतरिक नीति में हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि बाह्य नीति में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैनिक दृष्टि से भारत की प्रतिष्ठा स्थापित करने का श्रेय मिलता है।

### आर्थिक नीति

भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लालबहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया 'जय जवान, जय किसान' का नारा सैन्य सुरक्षा एवं खाद्य सुरक्षा के बीच आंतरिक संबंधों को रेखांकित करता है। वस्तुतः 1960 के दशक में भारत पीएल-480 के तहत अमेरिकी खाद्यान्न सहायता पर निर्भर था, किंतु अमेरिका के द्वारा आर्थिक सहायता रोकने जाने की प्रतिक्रिया में भारत ने खाद्य सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन के लिये खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। इसके तहत लालबहादुर शास्त्री की सरकार ने हरित क्रांति की नींव डाली, परंतु वास्तविक रूप में इसका क्रियान्वयन श्रीमती इंदिरा गाँधी के काल में हुआ क्योंकि इसका प्रभाव एक दशक बाद दिखलाई पड़ा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन और मैक्सिको के नॉर्मन बोरलॉग के सहयोग से उच्च पैदावार वाली गेहूँ की प्रजाति के बीज को आयात किया गया। साथ ही, रासायनिक खाद, कीटनाशक एवं व्यापक सिंचाई के माध्यम से हरित क्रांति को आगे बढ़ाया गया।

हरित क्रांति के कई लाभ भारत को मिले। खाद्यान्नों का उत्पादन 50 मिलियन टन से बढ़कर 180 मिलियन टन हो गया, औद्योगीकरण को प्रोत्साहन मिला तथा खाद्यान्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन गया।

### विदेश नीति

नेहरू के शीघ्र बाद शास्त्री जी को विदेश नीति में दो प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रथम- पाकिस्तान के आक्रमण का मुकाबला और दूसरा, परमाणु अप्रसार की नीति पर भारत का रुख तय करना।

भारत परमाणु अप्रसार की नीति का समर्थक था, किंतु जब तक विश्व में परमाणु हथियार नष्ट नहीं हो जाते, तब तक वह परमाणु अप्रसार का पूर्ण आश्वासन देने के लिए भी तैयार नहीं था या फिर परमाणु हथियार बनाने के अपने अधिकार को

औपचारिक रूप में नहीं छोड़ना चाहता था। परंतु जब 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिया, तो भारतीय सरकार पर विभिन्न दलों के द्वारा परमाणु हथियार बनाने के लिए दबाव पड़ने लगा। परन्तु लाल बहादुर शास्त्री परमाणु हथियार बनाने के पक्ष में नहीं थे। बदले में वे चीन के परमाणु हथियारों के विरुद्ध भारत के पक्ष में अमेरिका की गारंटी चाहते थे। लेकिन उस समय अमेरिका क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट से उत्पन्न स्थिति के कारण परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए संकल्पित था, इसलिए उसने स्वीकृति नहीं दी।

दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमेरिका से बड़ी संख्या में प्राप्त हथियारों से उत्साहित होकर 1965 में भारत पर आक्रमण कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने इस युद्ध में बहुत ही व्यावहारिक बुद्धि का परिचय दिया। हालांकि, यह युद्ध अनिर्णीत रहा, किंतु इस युद्ध में भारत का पलड़ा अधिक भारी था। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के कारण यह युद्ध समाप्त हुआ। फिर जनवरी, 1966 में सोवियत रूस की मध्यस्थता में लाल बहादुर शास्त्री एवं जनरल अयूब खान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। इस समझौते के निम्नलिखित मुख्य बिंदु थे-

1. भारत-पाकिस्तान शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगे।
2. दोनों देश 25 फरवरी, 1966 तक अपनी सेनाएं 5 अगस्त, 1965 की सीमा रेखा पर पीछे हटा लेंगे।
3. इन दोनों देशों के बीच आपसी हित के मामलों में शिखर वार्ताएँ तथा अन्य स्तरों पर वार्ताएँ जारी रहेंगी।
4. दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बंध फिर से स्थापित किए जाएंगे।

लाल बहादुर शास्त्री की उत्तराधिकारी इंदिरा गाँधी हुईं। सत्ता में आने के बाद उसके समक्ष एक बड़ी चुनौती थी विदेश नीति। उन्होंने भारत की विदेश नीति में यथार्थवाद को प्रोत्साहन दिया।

जिस समय उन्होंने भारत की बागडोर संभाली थी, उसी समय उन्हें पश्चिमी साम्राज्यवाद का कड़वा आस्वाद मिल गया। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों का दबाव भारत पर था कि भारत अपने रूपये का अवमूल्यन करे। अतः सत्ता में आने के 4 महीने के अंदर ही उन्होंने भारतीय मुद्रा में 35.5% का अवमूल्यन कर दिया, किंतु अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत को सहायता नहीं मिल सकी।

इंदिरा गाँधी ने परमाणु हथियार के मुद्दे पर भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर

करने से स्पष्ट मना कर दिया क्योंकि यह पक्षपातपूर्ण थी। फिर 1974 में पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया और इसका शांतिपूर्ण उद्देश्य घोषित कर दिया।

इंदिरा गाँधी की विदेश नीति का एक पक्ष वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के संदर्भ में भारत के रूख को स्पष्ट करना भी था। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरण के मसले पर आयोजित प्रथम विश्व सम्मेलन में इंदिरा गाँधी ने घोषित किया था कि 'गरीबी, पर्यावरण की सबसे बड़ी दुश्मन है' (Poverty is the worst polluter)।

#### ■ बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम:

इंदिरा गाँधी की विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती थी 1971 का भारत-पाक युद्ध तथा बांग्लादेश का निर्माण। वस्तुतः 1971 में पाकिस्तान में हुए चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के नेता मुजीबुर्रहमान तथा उसकी पार्टी आवामी लीग को बड़ी सफलता मिली। इसके बावजूद सैनिक जनरल याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने आवामी लीग को सरकार नहीं बनाने दी। इसके विरोध में आवामी लीग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया, तो फिर पाक की सरकार ने उसका उग्र दमन आरंभ कर दिया। मुजीबुर्रहमान को गिरफ्तार करके एक अज्ञात जगह पर ले जाया गया। पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहनी सेना का गठन हुआ, ताकि पाक के क्रूर दमन का सामना किया जा सके।

• भारत द्वारा बांग्लादेश के उदय में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदार परिस्थितियाँ:-

1. पूर्वी पाकिस्तान में हो रहा नरसंहार:- इसने भारत की पूर्वी सीमा को विचलित कर दिया था। साथ ही, वहाँ की

जनता के द्वारा भारत से बार-बार सहायता की माँग करना भी भारत द्वारा मानवता के नाम पर हस्तक्षेप करने में उत्तरदायी कारक रहा था।

2. शरणार्थियों की समस्या:- पूर्वी पाकिस्तान की सीमा भारत से जुड़ी है तथा वहाँ पर पाक सेना के दमन तथा वहाँ की बदतर परिस्थितियाँ जनता को भारत जाने के लिए विवश करती थीं। शरणार्थियों के आने से उत्तर-पूर्व के राज्यों, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में असंतुलन सा आ गया था, जिसके समाधान के क्रम में इंदिरा गाँधी की सरकार को इस ओर कदम बढ़ाना पड़ा।

3. पाकिस्तानी वायुसेना का आक्रमण:- पाकिस्तानी वायुसेना के द्वारा 2 दिसंबर, 1971 को भारतीय वायुसेना के कई हवाई अड्डों पर हमले किए गए, जिसकी वजह से भारत को युद्ध के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि भारत इसके लिए पहले से ही तैयार था, तभी उसने युद्ध को दोनों सीमाओं यथा-पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा पर आरंभ किया तथा 16 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा आत्मसमर्पण के बाद एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी। फिर पाक के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गाँधी के मध्य शिमला समझौता हुआ। इस समझौते में पाक के साथ रियायत बरती गई, सिवाय लद्दाख और लेह के बीच छोटे से भू-भाग को छोड़कर पाकिस्तान को सारा क्षेत्र वापस कर दिया गया तथा दोनों के बीच यह भी समझौता हुआ कि अब कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में नहीं, अपितु द्विपक्षीय वार्ता से होगा।